

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	'ई-नाम प्लेटफॉर्म' पर राजस्थान का प्रदर्शन
2.	बिकाजी फूड्स के संस्थापक शिव रतन अग्रवाल का निधन
3.	रावतभाटा-राज एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड (RRAEL)
4.	राजस्थान में पीएम-कुसुम योजना के संयंत्रों की कुल क्षमता : 4000 MW
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. नवनीतलाल निनामा (बाँसवाड़ा) का निधन 2. RSLDC और यूनिसेफ इंडिया के मध्य बालिका शिक्षा संबंधी लेटर ऑफ इंटेंट 3. RSLDC एवं फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ राजस्थान (FDCR) के मध्य 4. राज्य का पहला बटरप्लाई पार्क : उदयपुर 5. 'मैने कभी चिड़िया नहीं देखी' : DIFF - 2026 के लिए चयनित 6. राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर : डीडवाना-कुचामन 7. दुनिया का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस सेट
6.	सूचना युद्ध, आधुनिक युग में युद्ध के बदलते स्वरूप का प्रतीक
7.	फ्लेक्स फ्यूल वाहन (FFVs)
8.	प्रधानमंत्री इंटरनेट शिप योजना (PMIS)
9.	अटल पेंशन योजना
10.	प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन (TDIP) योजना
11.	भारत-श्रीलंका गोताखोरी अभ्यास (DIVEX 2026)
12.	"अत्यधिक गर्मी और कृषि" शीर्षक से रिपोर्ट जारी



राजस्थान परिदृश्य



'ई-नाम प्लेटफॉर्म' पर राजस्थान का प्रदर्शन



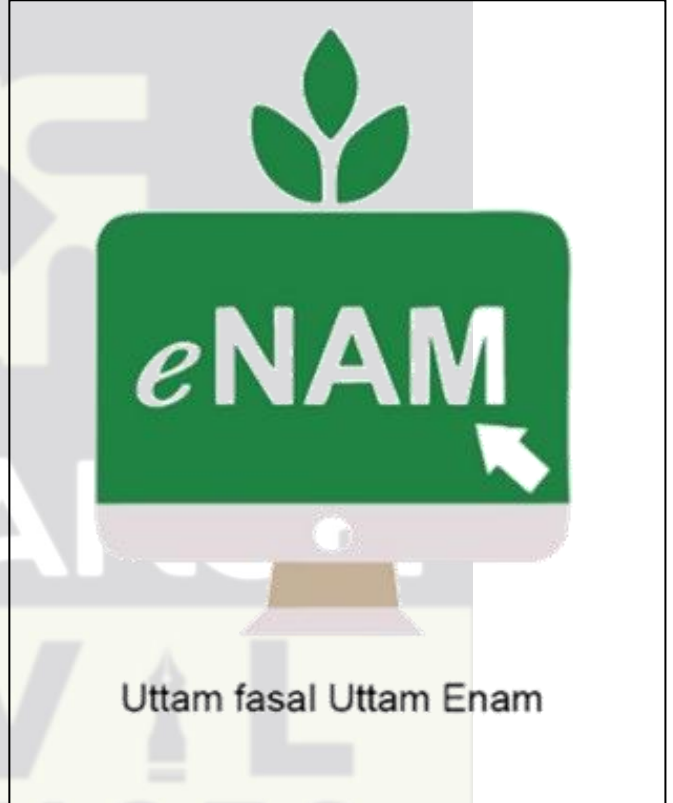
चर्चा में क्यों?

- अप्रैल, 2026 तक के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, विगत 10 वर्षों के दौरान राजस्थान 'ई-नाम प्लेटफॉर्म' पर कुल आवक (कृषि उपज का प्लेटफॉर्म पर आगमन) के मामले में देश भर में दूसरे एवं ई-ट्रेड में प्रथम स्थान पर रहा है। (स्रोत - DIPR & GoR, X)



मुख्य बिन्दु:

- वर्तमान में सम्पूर्ण राजस्थान में 173 मंडियाँ ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है, जिनमें से 134 ई-नाम मंडियाँ कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जाँच के लिए AI/ML - आधारित मशीनों का उपयोग कर रही हैं। ई-नाम के जरिए राजस्थान में 138 वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है।
- साथ ही, राजस्थान में 546 किसान-उत्पादक संगठन (FPOs) ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं।
- **ई-भुगतान में राजस्थान :** राजस्थान में ई-नाम प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान प्रणालियों को प्रोत्साहित करता है, जिससे किसानों के वित्तीय समावेशन में मदद मिल रही है। ई-भुगतान में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर रहा है।



Daily Current Affairs

Date : 24 April, 2026



- ज्ञातव्य है कि राजस्थान में ई-नाम प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 'ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना' को 'कृषक उपहार योजना' में शामिल किया गया है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) :

- **शुरुआत :** ई-नाम 14 अप्रैल, 2016 को शुरू किया गया एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है।
- **कार्यान्वयन :** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) द्वारा।
- **कार्यप्रणाली :** यह ऑनलाइन पोर्टल/ऐप के माध्यम से एआई-आधारित गुणवत्ता परीक्षण, ई-बोली (e-bidding) और ऑनलाइन भुगतान प्रदान करता है।
- यह देश भर की कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) को एक मंच पर जोड़कर, पारदर्शी तरीके से, बेहतर मूल्य खोज और "एक राष्ट्र, एक बाजार" के विज़न के साथ कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
- **ई-नाम 2.0 :** केन्द्र सरकार द्वारा 12 फरवरी, 2026 से लागू।
- इस नए प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वचालित बोली प्रणाली, मांग-आपूर्ति डेटा, लॉजिस्टिक्स और फिनटेक सहायता जैसी सुविधाओं के द्वारा अंतर-राज्यीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देना है।

--3--

बिकाजी फूड्स के संस्थापक शिव रतन अग्रवाल का निधन

चर्चा में क्यों?

- बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के संस्थापक, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिव रतन अग्रवाल का 23 अप्रैल, 2026 को चेन्नई में निधन हो गया।



मुख्य बिन्दु:

- बिकाजी भारत की अग्रणी फास्ट - मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनियों में से एक है, जो मुख्य रूप से बीकानेरी भुजिया, नमकीन, पापड़ और पारंपरिक मिठाइयों का निर्माण करती है।
- वर्ष 1986 : शिव रतन अग्रवाल द्वारा बीकानेर में 'शिवदीप फूड्स प्रोडक्ट्स' के नाम से शुरुआत।
- वर्ष 1993 : 'शिवदीप फूड्स प्रोडक्ट्स' का नाम 'बिकाजी' रखा गया।
- वर्ष 1994 : बिकाजी ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पहला निर्यात कर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत की।

--:4:--

Daily Current Affairs

Date : 24 April, 2026



- वर्ष 2010 : बिकाजी की 'बीकानेरी भुजिया' को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्रदान किया गया।
 - वर्ष 2014 : कंपनी ने पहली बार प्राइवेट इक्विटी के जरिए फंड हासिल किया।
 - वर्ष 2019 : अमिताभ बच्चन को बिकाजी का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया।
 - वर्ष 2022 : बिकाजी का IPO आया और कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई।
- पुरस्कार :
- वर्ष 2008 : राजस्थान स्टेट अवॉर्ड फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस।
 - वर्ष 2009 : गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्टेट अवॉर्ड फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस।



--:5:--

रावतभाटा-राज एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड (RRAEL)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, अडानी ग्रुप ने 'रावतभाटा-राज एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड' (RRAEL) नाम से एक नई सहायक कंपनी का गठन किया।



मुख्य बिन्दु:

- RRAEL 'अडानी पावर लिमिटेड' की एक स्टेप-डाउन सहायक कंपनी है। यह 'अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड' (AAEL) के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
- इस कंपनी का मुख्य लक्ष्य भारत में परमाणु स्रोतों से बिजली का उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण करना है।

Daily Current Affairs

Date : 24 April, 2026



- अडानी ग्रुप द्वारा इस कंपनी की स्थापना भारत सरकार द्वारा लाए गए SHANTI विधेयक (2025) के बाद हुई है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- **SHANTI विधेयक** : सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल, 2025
- यह विधेयक परमाणु क्षेत्र को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोलता है। इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक परमाणु क्षमता को वर्तमान 8.8 GW से बढ़ाकर 100 GW करना है।
- **उद्देश्य** : परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 का स्थान लेकर परमाणु ऊर्जा के निर्माण, संचालन और उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना (RAPP)

- चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (RAPP) राज्य का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसमें 7 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWR) इकाइयाँ संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 1780 MW है।
- **शुरुआत** : दिसम्बर, 1973 (सहयोग - कनाडा)।
- **संचालन** : न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)

--7--

राजस्थान में पीएम-कुसुम योजना के संयंत्रों की कुल क्षमता : 4000
MW



चर्चा में क्यों?

- अप्रैल, 2026 तक पीएम-कुसुम योजना के तहत, राजस्थान में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 4,000 मेगावाट (MW) तक पहुँच चुकी है। (स्रोत - DIPR & GoR, X)

The infographic features a central portrait of a man in a blue shirt and patterned shawl. To his left, the text reads '4 हजार मेगावाट के स्तर पर पहुंची पीएम-कुसुम परियोजनाएँ' (4 thousand megawatts level reached by PM-Kusum projects). Above the text is a sun icon with a lightning bolt, and below it is a solar panel icon. To the right of the portrait is the Rajasthan State Emblem and the text 'सत्यमेव जयते राजस्थान सरकार' (Truth alone triumphs, Rajasthan Government). At the bottom, there are two photographs: one showing a large solar panel array in a field, and another showing a solar panel array with rows of green plants growing between them.

--8--



मुख्य बिन्दु:

- राज्य में इस योजना के तहत अब तक 1,808 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
- राजस्थान पीएम - कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए में देश में पहले स्थान पर है, जबकि कम्पोनेंट-सी में तीसरे स्थान पर है।

पीएम कुसुम:

- **शुरुआत** : मार्च, 2019
- **नोडल मंत्रालय** : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
- **उद्देश्य** : किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा गैर-जीवाश्म आधारित स्रोतों से विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करना।

योजना के तीन घटक (Components):

कम्पोनेंट-ए:

- 500 किलोवाट (kW) से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले व्यक्तिगत संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से 10,000 मेगावाट सौर क्षमता की स्थापना करना।
- ट्रांसमिशन लाइनों की उच्च लागत और नुकसान से बचने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों को अधिसूचित सब-स्टेशनों के पाँच किलोमीटर के दायरे में स्थापित करना।
- उत्पादित विद्युत की खरीद स्थानीय डिस्कॉम (Distribution Company) द्वारा संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) द्वारा निर्धारित पूर्व-निर्धारित टैरिफ पर की जाती है।
- **नोट** : राजस्थान में कम्पोनेंट-ए का कार्यान्वयन प्रारंभ में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL) द्वारा किया जा रहा था, जिसे 23 जुलाई, 2024 को राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान डिस्कॉम्स को हस्तांतरित कर दिया गया।

कम्पोनेन्ट-बी:

- 20 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना।
- इस घटक के तहत 3 से 10 हॉर्सपावर (HP) तक के स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें 7.5 हॉर्सपावर तक के पंपों के लिए अधिकतम अनुदान देय है।
- जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि बिजली कनेक्शन नहीं है और जो डीजल आधारित पंप सेट पर निर्भर हैं, वे इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप प्रणाली स्थापित करने के पात्र हैं।
- इस योजना के अन्तर्गत किसानों का हिस्सा 40 प्रतिशत है। शेष 60 प्रतिशत भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बराबर-बराबर 30-30 प्रतिशत दिया जाता है।
- 40 प्रतिशत में से किसान बैंक से 30 प्रतिशत तक ऋण ले सकता है और शेष 10 प्रतिशत किसानों को देना होगा।
- योजना के कम्पोनेन्ट-बी का क्रियान्वयन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

कम्पोनेन्ट-सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन)

- नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 4 दिसम्बर, 2020 को पीएम-कुसुम योजना के घटक C के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिसमें ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता जो एक या एक से अधिक अलग-अलग कृषि फीडरों की वार्षिक बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए कैपेक्स मोड या रेस्को मोड के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है।
- मंत्रालय ने 4,00,000 पम्प सेटों का सोलराइजेशन करने का लक्ष्य स्वीकृत किया है।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>नवनीतलाल निनामा (बाँसवाड़ा) का निधन</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, भाजपा के वरिष्ठ नेता और बाँसवाड़ा की घाटोल विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे नवनीत लाल निनामा का निधन हो गया।वे भारतीय जनसंघ और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।उन्होंने चार बार (1977, 1980, 1990 और 2003) घाटोल विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया।
2.	<p>RSLDC और यूनिसेफ इंडिया के मध्य बालिका शिक्षा संबंधी लेटर ऑफ इंटेन्ट</p> <ul style="list-style-type: none">राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) और यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में राजस्थान में महिला सशक्तीकरण संबंधी एक लेटर ऑफ इंटेन्ट (LoI) पर हस्ताक्षर किए।उद्देश्य : बालिकाओं के डिजिटल सशक्तीकरण एवं रचनात्मक क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देना।इस प्रोजेक्ट के तहत 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 2,000 युवतियों को अल्पावधि डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है।यह कार्यक्रम मार्च, 2027 तक चरणबद्ध रूप से संचालित किया जाएगा तथा परिणाम-आधारित मॉडल के तहत सफल प्लेसमेंट के उपरांत भुगतान किया जाएगा।

3.	<p>RSLDC एवं फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ राजस्थान (FDCR) के मध्य</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) और फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ राजस्थान (FDCR) के बीच हाल ही में एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।■ समझौते का उद्देश्य : फैशन, टैक्सटाइल, डिजाइन, फिल्म, मीडिया एवं अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।■ इसके अंतर्गत प्रशिक्षण, मास्टर क्लास, उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम, इंटरशिप एवं स्टार्टअप अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
4.	<p>राज्य का पहला बटरप्लाई पार्क : उदयपुर</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान का पहला बटरप्लाई पार्क उदयपुर के अम्बेरी स्थित मेवाड़ जैव विविधता पार्क में स्थापित किया गया है।■ लगभग दो हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए इस पार्क में 80 प्रजातियों की रंग-बिरंगी तितलियाँ हैं।■ इस पार्क में 'जेब्रा स्किपर' तितली है, जो पूरे भारत में केवल यहीं पाई जाती है।
5.	<p>'मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी' : DIFF - 2026 के लिए चयनित</p> <ul style="list-style-type: none">■ जयपुर निवासी ऊषा दशोरा की फिल्म "मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी" को दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (DIFF) - 2026 के लिए चुना गया।■ हिंदी और राजस्थानी भाषा में निर्मित 70 मिनट की इस फिल्म का विषय बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण चेतना पर केंद्रित है, जिसमें बच्चों के मन में पक्षियों, प्रकृति और धरती के प्रति जिज्ञासा और संवेदनशीलता को उकेरा गया है।■ DIFF का आयोजन : 4 से 8 मई, 2026 तक इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र (संस्कृति मंत्रालय) द्वारा डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में।

6.	<p>राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर : डीडवाना-कुचामन</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर डीडवाना-कुचामन में स्थापित किया गया है।■ इस परिसर का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके आश्रितों को सैनिक कल्याण से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।
7.	<p>दुनिया का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस सेट</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी डॉ. इकबाल सक्का ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस सेट बनाया।■ इस टेबल का आकार मात्र 4×3 मिलीमीटर है और बॉल का आकार आधा मिलीमीटर है।■ इस उपलब्धि को 'होप इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक' में दर्ज किया गया है।





राष्ट्रीय परिदृश्य



सूचना युद्ध, आधुनिक युग में युद्ध के बदलते स्वरूप का प्रतीक



चर्चा में क्यों?

- सूचना युद्ध (Information Warfare) तेजी से वायु, थल और जल के अलावा युद्ध के चौथे आयाम के रूप में उभर रहा है।



मुख्य बिन्दु:

- भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' से लेकर वर्तमान में जारी अमेरिका-ईरान युद्ध तक इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं।

सूचना युद्ध

- **परिभाषा:** सूचना युद्ध वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त हासिल करने के लिए जानकारी का संग्रह, प्रसार, संशोधन, व्यवधान, हस्तक्षेप, भ्रष्ट करना और क्षति पहुँचाना शामिल होता है।

--:14:--

- इसमें डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जनमत, राजनीतिक विमर्श और सामाजिक मानदंडों में हेरफेर करने और उन्हें प्रभावित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ:

- **दुष्प्रचार:** एडिट की गई तस्वीरें और AI की मदद से वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह करना।
- **फेक न्यूज़ फैलाना:** झूठी खबरों को वास्तविक खबर की तरह प्रस्तुत करना।
- **सोशल मीडिया एल्गोरिदम का दुरुपयोग:** चुनिंदा कंटेंट्स को अधिक प्रसारित करने और उसकी पहुँच व दृश्यता को नियंत्रित करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करना।

विशेषताएं:

- कम लागत में व्यापक प्रभाव,
- युद्ध में जीत-हार की धारणा को प्रभावित करना,
- जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना।
- पारंपरिक खुफिया तंत्र प्रायः उपर्युक्त खतरों का पता लगाने में संघर्ष करता है।

सूचना युद्ध और भारत

- **भारत की कमियाँ:** भारत का सूचना युद्ध के प्रति दृष्टिकोण बहुत हद तक प्रतिक्रियात्मक है। यह मुख्यतः रोकथाम, डिफेन्स और तथ्य-जांच पर केंद्रित रहता है, बजाय इसके कि सक्रिय रूप से रणनीति बनाकर पहले से कदम उठाए जाएँ।

भारत में सूचना युद्ध से निपटने के लिए की गई प्रमुख पहलें

- **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम:** जैसे- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन।
- **सैन्य तैयारी:** जैसे- भारतीय सेना में 'सूचना-युद्ध महानिदेशक' (Director General Information Warfare) पद का सृजन।
- **अन्य पहलें:** PIB फैक्ट-चेक यूनिट और व्हाट्सएप चैटबॉट, सरकारी सोशल मीडिया और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों का गठन।

आर्थिक घटनाक्रम

फ्लेक्स फ्यूल वाहन (FFVs)

चर्चा में क्यों?

- भारत आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को तेजी से अपनाने पर विचार कर रहा है।



मुख्य बिन्दु:

फ्लेक्स फ्यूल वाहनों (FFVs):

- FFVs संशोधित वाहन हैं। ये वर्तमान में पूरी तरह से केवल गैसोलीन या गैसोलीन और इथेनॉल के किसी भी मिश्रण (83% या E83 तक) पर चलने में सक्षम हैं।
- आधुनिक FFVs को अब इस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है कि वे उच्च इथेनॉल मिश्रणों, जैसे E100 (शुद्ध एथेनॉल), पर भी चल सकें।
- इनमें सामान्य पेट्रोल-वाहनों की तरह ही पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन होता है। लेकिन इनमें इथेनॉल के अनुकूल फ्यूल सिस्टम और अलग प्रकार का पावरट्रेन कैलिब्रेशन होता है, जिससे ये पेट्रोल के साथ-साथ इथेनॉल मिश्रण पर भी सुचारू रूप से चल सकें।
- उच्च इथेनॉल मिश्रणों पर चलते समय ये बेहतर ऐक्सीलरेशन परफॉरमेंस दर्शाते हैं।

--:16:--

योजनाएँ एवं नीतियाँ

प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना (PMIS)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए पात्रता मानदंडों का विस्तार किया है। अब इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है।



मुख्य बिन्दु:

प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना:

- **प्रारंभ:** इस योजना का प्रायोगिक चरण अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था, जो केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के बाद हुआ था।
- **उद्देश्य:** देशभर के युवाओं को शीर्ष कंपनियों में व्यवस्थित और सवेतन इंटरशिप के अवसर प्रदान करना जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव और कौशल विकास में मदद मिले।
- प्रशिक्षुओं को प्रति माह न्यूनतम ₹9,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
- **इंटरशिप की अवधि:** इंटरशिप की प्रकृति के आधार पर 6 या 9 महीने।
- **लाभार्थी:** 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं।

अटल पेंशन योजना



चर्चा में क्यों?

- अटल पेंशन योजना ने 21 अप्रैल, 2026 को कुल 9 करोड़ ग्राहकों के नामांकन का आंकड़ा पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।



मुख्य बिन्दु:

अटल पेंशन योजना

- यह भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका संचालन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है।
- 2015 में शुरू की गई यह योजना एक स्वैच्छिक, अंशदायी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है।
- यह 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है, सिवाय उन लोगों के जो आयकर दाता हैं या रह चुके हैं।
- इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ग्राहकों को 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती थी।



प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन (TDIP) योजना

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संशोधित योजना को 2026-31 की अवधि के लिए कुल ₹203 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य वैश्विक दूरसंचार मानक-निर्धारण प्रक्रियाओं में भारत की भागीदारी और प्रभाव को बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य 5जी एडवांस्ड और 6जी जैसी अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है।
- यह योजना भारतीय हितधारकों को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, थर्ड जेनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट (3GPP) और वनएम2एम जैसे वैश्विक दूरसंचार निकायों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र की भागीदारी के लिए विस्तारित दायरा:** संशोधित दिशानिर्देशों ने योजना के दायरे को काफी हद तक विस्तारित किया है, जिसमें स्टार्टअप, एमएसएमई, अकादमिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान, दूरसंचार सेवा प्रदाता और उद्योग जगत के खिलाड़ी शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी, भारत (TSDSI), भारत का दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र (TCoE) और टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (TCIL)।



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



भारत-श्रीलंका गोताखोरी अभ्यास (DIVEX 2026)



मुख्य बिन्दु:

- भारत- श्रीलंका DIVEX 2026 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए आईएनएस निरीक्षण कोलंबो पहुंचा।
- DIVEX एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो विशेषीकृत जलमग्न संचालन और पनडुब्बी बचाव प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच अंतरसंचालनीयता, परिचालन समन्वय और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाना है।
- यह अभ्यास समुद्री सहयोग को गहरा करने को दर्शाता है और भारत की महासागर परिकल्पना के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करता है।

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

"अत्यधिक गर्मी और कृषि" शीर्षक से रिपोर्ट जारी

चर्चा में क्यों?

- FAO और WMO ने "अत्यधिक गर्मी और कृषि" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अत्यधिक गर्मी वैश्विक और भारतीय कृषि-खाद्य प्रणाली को गंभीर संकट की ओर धकेल रही है।

मुख्य बिन्दु:

भारतीय कृषि के संबंध में रिपोर्ट में मुख्य बिंदु

- **खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा:** लू भारत में चावल और गेहूं उत्पादन के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं, खासकर गंगा और सिंधु नदी बेसिन क्षेत्रों में जोखिम सबसे अधिक है।
- साथ ही, लू बढ़ने के साथ कीट हमलों में वृद्धि, बीमारियों के प्रकोप, वर्षा की कमी जैसे संकट उत्पन्न होंगे। इससे फलों, सब्जियों, डेयरी और पोल्ट्री की पैदावार में तेजी से गिरावट आ सकती है।
- **कृषि श्रमिकों के लिए खतरे:** उच्च उत्सर्जन की स्थितियों में 21वीं सदी के अंत तक, तापमान की चरम स्थितियों के कारण कार्य करने की क्षमता में लगभग 40% तक कमी आ सकती है।

प्रमुख सुझाव और अनुकूलन रणनीतियाँ

खेत-स्तर पर सुधार और नवाचार:

- गर्मी-सहिष्णु फसलें और पशु नस्लें विकसित करना,
- बुवाई के समय में बदलाव करना,
- बेहतर सिंचाई और शेडिंग जैसी प्रबंधन तकनीकें अपनाना।

--:21:--

Daily Current Affairs

Date : 24 April, 2026



- **पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ:** मौसमी पूर्वानुमान जैसी प्रणालियाँ किसानों को जोखिम का पहले से अनुमान लगाने और सुरक्षा उपाय अपनाने में मदद करती हैं।
 - **वित्तीय सेवाओं तक पहुँच:** कैश ट्रांसफर, फसल बीमा और विपदाओं को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं संकटग्रस्त किसानों के लिए अत्यंत जरूरी हैं, ताकि वे अत्यधिक गर्मी से हुए नुकसान की भरपाई कर सकें और गरीबी के दुष्चक्र में फंसने से बच सकें।
 - **जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय:** वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च उत्सर्जन वाली आर्थिक प्रणालियों को त्यागने की आवश्यकता है।
- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)**
- **स्थापना:** 1945 में स्थापित FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संगठन भुखमरी से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है।
 - **मुख्यालय:** रोम, इटली।
 - **सदस्य:** 194 सदस्य (193 देश और यूरोपीय संघ)। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है।
 - **प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट्स:** द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)**
- **स्थापना:** 1950 में स्थापित WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संगठन मौसम विज्ञान, सक्रिय हाइड्रोलॉजी और संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
 - WMO का उद्भव 1873 में स्थापित 'अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन' (IMO) से हुआ है।
 - **सचिवालय:** जिनेवा।
 - **सदस्य:** भारत सहित 193 (187 सदस्य देश और 6 प्रादेशिक क्षेत्र)।
 - **प्रमुख पहलें:** 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के साथ मिलकर 'जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)' की सह-स्थापना की।

--:22:--